नई सोच, नया आयाम

जोहार छत्तीसगढ़

दैनिक हिन्दी

RNI No. CHHHIN/2009/35020

◆ वर्षः -14 ◆ अंकः 230 डाक पंजीयन 030/रायगढ़/2015-2017 ◆ मूल्यः 2 ₹ ◆ पृष्ठ : 4

धरमजयगढ़, बुधवार 29 जून 2022

पेज -3 पर जशपुर जिले में प्रदेश का पहला उच्च स्तरीय फूड प्रोसेसिंग ...

कांग्रेस भाजपा के बीच अविश्वास प्रस्ताव का खेल महासमुंद ... पेज -4 पर

JOHAR CHHATTISGARH epaper for login www.joharchhattisgarh.in

एक नजर

ईडी,सीबीआई पर सियासी बवाल

भाजपा ने नहीं बनाई ईडी जो सीबीआई का दुरुपयोग करेगी, लगता है कांग्रेसियों ने किया है- कौशिक

रायपुर। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ED के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। नेशनले हेराल्ड मामले में हाल ही पूछताछ हुई है। अब कांग्रेस ने इन संस्थाओं के सियासी इस्तेमाल का आरोप भाजपा पर लगाया। इस मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बयान दिया। मंगलवार को इस मामले में मीडिया में जवाब देते हुए उन्हांने कांग्रेस को घेरा।

कौशिक ने कहा कि CBI, ED को भाजपा ने नहीं बनाया, न ही इनका गठन किया। ये संस्थाएं पहले से काम कर रही हैं। देश में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक थी, उस समय ईडी काम नहीं कर रही थी क्या, उस समय क्यों बयान नहीं दिए कांग्रेस के नेता। अब आपत्ति क्यों, कांग्रेस के नेता कह देते हैं कि इन संस्थाओं का किसी के लिए उपयोग किया है, लगता है कांग्रेसियों ने इन संस्थाओं का उपयोग किया है, तभी ऐसा कह रहे हैं। संवैधानिक संस्था को बदनाम करना कांग्रेस की आदत है।

500 करोड़ वापस पाने निवेशकों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

बिलासपुर। सहारा इंडिया सोसायटी से भुगतान की मांग को लेकर निवेशकों ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले निवेशकों ने बिलासपुर में आंदोलन भी किया।

लेकिन, फिर भी उनके 500 करोड़ रुपए जमा राशि नहीं लौटाई गई। याचिका में सोसायटी प्रमुख सुब्रत रॉय, RBI, SEBI सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है।

सहारा इंडिया सोसायटी के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे परेशान होकर अविनाश दार्वेकर, याजुवेंद्र त्रिवेदी, नारायण मूर्ति, अशोक बासु, बनानी घोष, पुर्शोत्तन श्रीवास, सूबेदार यादव और अन्य ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ता डॉ. सचिन अशोक काले एवं अन्य वकीलों ने कोर्ट

को बताया कि सहारा इंडिया सोसायटी के अफसर सेबी सहारा विवाद के कारण भुगतान में देरी होने का हवाला दे रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सेबी की ओर से खुद बताया गया है कि इस विवाद में सेबी को कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद भी सहारा

प्रदर्शन करने के बाद भी सहारा इंडिया ने नहीं लौटाए पैसे, 4 हफ्ते बाद सुनवाई

सोसायटी के अफसर जानबूझकर झूठे तथ्यों को भोली भली जनता को बताकर बरगलाया रहे हैं और जमाकर्ताओ की राशि में हेराफेरी की जा रही है। याचिकाकर्ता ने बताया कि सहारा इंडिया सोसायटी ने बिलासपुर जिले से करीब 500 करोड़ रुपए अपनी योजनाओ में जमा कराया है, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद भी जमाकर्ताओं को उनकी राशि नहीं दी जा रही है। ऐसे में हजारों निवेशक परेशान हैं। वहीं, अफसर जमाकर्ताओं को उनकी ही राशि लौटाने में तरह-तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। सहारा सोसायटी से भुगतान की मांग को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आन्दोलन हो रहे हैं और अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। बिलासपुर में भी सहारा जमाकर्ता कार्यकर्त्ता मंच की ओर से राशि भुगतान की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किया जा चुका है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अपने भुगतान को लेकर आवेदन दिया।

छत्तीसगढ़ में फिर लौटी कोरोना की सख्ती

प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर होगी कोविड जांच; बॉर्डर चेकपोस्ट पर टीम तैनात होगी

रायपुर. कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद छत्तीसगढ़ में सख्ती भी लौट आई है। सरकार ने अब सभी हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करने को कहा है। बार्डर चेकपोस्ट पर भी कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात करने को कहा गया है। कोरोना की तीसरी लहर बीतने के बाद सरकार ने हवाई अड्?डों पर जांच की अनिवार्यता वाला आदेश वापस ले लिया था।

स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना संदिग्ध 10268 नमूनों की जांच की। यह इस महीने एक दिन में हुई सबसे अधिक नमूनों की जांच थी। इस दौरान 125 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद सरकार हरकत में आई। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को एक दिशा-निर्देश जारी किया।

इसके अनुसार राज्य के सभी हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों का कोविड सैंपल चेकिंग करना है। इसी तरह अन्य राज्यों से अंतरराज्यीय बार्डर चेक पोस्ट के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य जांच टीम तैनात कर कोविड सैंपल चेकिंग करने को कहा गया है। अधिकारियों का इस निर्देश का पालन कड़ाई से करने का निर्देश दिया गया है।

अभी तीन हवाई अड्डों से अंतरराज्यीय परिवहन

छत्तीसगढ़ में अभी तीन हवाई अड्डों से अंतरराज्यीय परिवहन हो रहा हैं। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्?डे से दूसरे प्रदेशों से यात्रियों का आना-जाना लगा हुआ है। रायपुर हवाई अड्?डे पर ही रोजाना औसतन 50 से अधिक उड़ानों का आना-जाना हो रहा है। इससे औसतन करीब 3-4 हजार यात्री रोज आते हैं।

सरकार को पहले से पता है यात्रियों की वजह से बढ़ रहा है संक्रमण

सरकार को इस महीने के दूसरे सप्ताह में ही पता चल गया था कि भीड़वाले और दूसरे राज्यों से लौटे लोगों की वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। मरीजों की हिस्ट्री में यात्राओं की जानकारी आई थी।

रायपुर में विदेशी लड़कियों के डांस पर हंगामा

बजरंग दल ने किया विरोध

रायपुर. रायपुर में बैली डांसर्स के कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया। होटल सयाजी में इस डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विदेशी लड़कियों को बुलाया गया था। अब इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में विदेशी डांसर्स परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के नेताओं ने विरोध कर दिया। बवाल इतना बढ़ा कि आयोजकों को इवेंट बंद करवाना पड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में इस कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत की थी। मगर इसके बाद भी होटल वालों ने इवेंट कराया तो दल के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए। यहां नारे बाजी करते हुए होटल में घुसने की कोशिश की। होटल वालों को फौरन पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस और बजरंग दल के नेताओं के बीच झूमाझटकी हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद होटल वालों को लिखित में देना पड़ा कि वो इस इवेंट को बंद करवा रहे हैं। बजरंग दल ज़िला संयोजक, रवि वाधवानी ने बताया कि ये अश्लील डांस हमारी संस्कृति के खिलाफ है।

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

19 जिलों के कलेक्टर सहित 37 IAS का ट्रांसफर, सौरभ कुमार की जगह सर्वेश्वर भूरे संभालेंगे राजधानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस साल का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) संवर्ग के 37 अफसरों का तबादला हुआ है। इसमें 19 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश से रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को अब बिलासपुर का कलेक्टर बना दिया गया है। वहीं सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को रायपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। भूरे अभी तक दुर्ग जिले के कलेक्टर थे।

कोरबा कलेक्टर रानू साहू को वहां से हटाकर रायगढ़ का कलेक्टर बना दिया गया है। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा को कोरबा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है।

राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को भी बदल दिया गया है। सिन्हा को अब जांजगीर-चांपा का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं बलौदा बाजार-भाटापारा के कलेक्टर रहे डोमन सिंह को राजनांदगांव की जिम्मेदारी मिली है। दुर्ग जिले की कमान पुष्पेंद्र कुमार मीणा को मिली है। मीणा अभी कोण्डागांव के कलेक्टर थे। इस फेरबदल से जिन जिलों के कलेक्टर प्रभावित हो रहे हैं उनमें, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, कांकेर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, दुर्ग, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सरगुजा, बलौदा बाजार-भाटापारा, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, बालोद, सुकमा, बलरामपुर-रामानुजगंज और मुंगेली शामिल है।

महिला से 90 हजार के जेवर की ठगी

रायपुर । अज्ञात दो लोगों ने एक महिला से 90 हजार रूपए की जेवर ठग लिए। प्रार्थिया की शिकायत पर गोलबाजार पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया मिलंतिन बाई यादव 58 वर्ष निवासी सिविल लाइन ने थाने में शिकायत किया कि जब वह कल दोपहर पैदल बाजार गई थी, तभी एक महिला व पुरूष उसके पास आए और नोटों की गड्डी दिखाकर झांसे में लिया कि इसे हम लोग आधा-आधा बांट लेंगे। जिससे प्रार्थिया उसके पीछे-पीछे मोतीबाग के तरफ गई। जिसके बाद आरोपियों ने उससे कहा कि ये सभी पैसा तुम रख लो उसके बदले तुम अपना पहने हुए जेवर दे दो। इस पैसे से और ज्यादा जेवर खरीद सकती हो। जिससे प्रार्थिया ने अपने पहने चांदी का करधन, सोने का मंगल सूत्र, सोने के टाप्स को उतारकर दे दिया।

जीएसटी में संरक्षित राजस्व खात्मे पर छत्तीसगढ़ को आपत्ति

टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र; कहा-गैर उपभोक्ता राज्यों को भारी नुकसान

रायपुर। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगले महीने से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। उसमें से एक है राज्यों के लिए 14% संरक्षित(रिजर्व) राजस्व अथवा क्षतिपूर्ति का खात्मा। यह व्यवस्था 30 जून से खत्म हो रही है। GST परिषद की बैठक से ठीक पहले छत्तीसगढ़ ने इसपर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को कम से कम पांच साल तक जारी रखने की मांग की है।

टीएस सिंहदेव ने लिखा है, 14% संरक्षित राजस्व का प्रावधान 30 जून 2022 से समाप्त हो जाएगा। इसे कम से कम 5

वर्षों तक जारी रखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ जैसे खनन और विनिर्माण राज्य, जो उपभोक्ता नहीं हैं, उनको बहुत अधिक राजस्व का नुकसान होता है।

सिंहदेव ने कहा है कि वे GST काउंसिल की बैठक में शामिल होना चाहते थे। 25 जून को वे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसकी वजह से वे बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सिंहदेव ने लिखा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री उनके पत्र को GST काउंसिल के समक्ष रखने की अनुमति दें और सुझावों को इस काउंसिल की बैठक के रिकॉर्ड में ले लिया जाए।

दहेज प्रताड़ना के जहर से विवाहिता की मौत

ससुराल वालों के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर । ग्राम चंगोरी में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली। मामले में नेवरा पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम चंगोरी निवासी मृतिका इंद्राणी टंडन 23 वर्ष से उसके ससुराल पक्ष के लोग आए दिन दहेज की मांग कर प्रताड़ित करते थे। वहीं उसका पति दीपक टंडन भी दहेज की मांग कर मारपीट करता था। जिससे तंग आकर महिला ने जहर सेवन कर लिया था। जिसे परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

समीक्षा.. 3 साल पहले हुआ था फैसला, अब जाकर 9623 युवाओं की नियुक्ति का रास्ता खुला

छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों को सरकारी नौकरी

रायपुर. सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के पढ़े-लिखे युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला अगस्त 2019 में हुआ था।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने

रविवार को जशपुर में यह घोषणा की। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को भर्ती की मंजूरी का आदेश जारी कर दिया।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सोमवार को बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर, सूरजपुर और बलौदाबाजार के कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2019 को जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में 'विशेष पिछड़ी जनजातियों' के शिक्षित और पात्र युवाओं का सर्वे कराकर नियुक्ति का फैसला हुआ था।

सर्वे के बाद जिलों में ऐसे शिक्षित युवाओं की संख्या 9 हजार 623 है। ऐसे में जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर 'विशेष पिछड़ी जनजाति' के पात्र युवाओं को सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आदेश के साथ विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं की सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है।

जब-जब घाटों पर छापा पड़ा, रेत की कीमत बढ़ी

रायपुर. रेत घाटों पर छापों के बाद कीमत कम होने के बजाय एक बार फिर से बढ़ गई है। छापों के पहले एक गाड़ी हाइवा 8000 से 10000 रुपए तक में मिल रही थी, लेकिन अब छापों के बाद यही 12000 से 14 हजार रुपए तक हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 2 साल में जब-जब रेत घाटों पर छापे पड़े, रेत की कीमत बढ़ गई। रेत सिंडीकेट का कहना है कि रेत घाटों से रेत निकालने का काम बंद हो गया है। अभी वही रेत दी जा रही है जिसका स्टॉक किया गया है। इस वजह से रेत की

कीमत बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने रेत घाटों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। लेकिन एक दिन की कार्रवाई के बाद मामला पूरी तरह से ठंडा हो गया। जिन गाड़ियों को पकड़ा गया था, उनसे जुर्माना लेकर उन सभी गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। प्रशासन की सख्ती का एक ये असर जरूर हुआ कि रेत घाटों पर अवैध खनन बंद हो गया है। अब जिले के मुख्य रेत घाटों कागदेही, पारागांव, चपरीद, चिखली, हरदीडीह समेत आसपास के सभी रेत घाटों से मशीनें हटा ली गई हैं।

रोजगार है असली समस्या

सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ एकदम से जो उबाल आया है वह देखने में भले तात्कालिक प्रतिक्रिया लगे लेकिन असल में युवाओं के रोष और हिंसक प्रदर्शन की जड़ें ज्यादा गहरी हैं। यह रोजगार को लेकर उनकी भविष्य की चिंता से जुड़ी है। पिछले दो साल से सेना में बहाली नहीं हो रही है तब भी नौजवान इस उम्मीद के साथ प्रतीक्षा और तैयारी कर रहे थे कि कभी न कभी तो बहाली शुरू होगी।

तभी जब नियमित बहाली की जगह चार साल तक ठेके पर नौकरी देने की योजना घोषित हुई तो युवाओं ने बेहद गुस्से में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी। वे सड़कों पर उतरें, रेलवे स्टेशनों पर तोड़-फोड़ की, गाड़ियां जलाईं, सड़कें जाम की और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के हरसंभव तरीके का इस्तेमाल किया। फिर अचानक तीन-चार दिन के हिंसक प्रदर्शन के बाद शांति बहाल हो गई। मान सकते हैं कि प्रदर्शन करने वाले युवाओं का एक बड़ा तबका वहीं चार साल की नौकरी हासिल करने की तैयारियों में लग गया होगा। क्योंकि उसके सामने नौकरी ओर रोजगार के विकल्प नहीं हैं।

वह सरकार की ओर से दिए गए तर्कों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन वह मजबूर है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जिस तरह की धमकी भरी भाषा में बात की गई उससे वह डरा भी। उसे अपना करियर खराब होने की चिंता हुई। वह मजबूरी में शांत

हुआ है। हताशा और नाउम्मीदी में उसने समझौता किया है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मौके आए, जब नाउम्मीद युवाओं ने इस तरह के हिंसक प्रदर्शन किए। इसी साल जनवरी में रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार में युवाओं ने बड़ा प्रदर्शन किया था और तब भी कई शहरों में रेलवे स्टेशनों पर तोड़-फोड़ हुई थी, ट्रेनें जलाई गई थीं। रेलवे परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन हुए थे। भर्ती बंद होना और नियमित रोजगार के अवसर लगातार कम होते जाना एकमात्र समस्या नहीं है, जिससे छात्र और युवा परेशान हैं। प्रश्न पत्र लीक हो जाना और नतीजों में धांधली की समस्याएं भी आम छात्रों को बहुत परेशान कर रही हैं।

वे इस मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं कि देश में नियमित नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। सरकारी विभागों में भर्ती या तो बंद है या बहुत कम हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बिक रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर घट रहे हैं। देश में बेरोजगारी की भयावह तस्वीर बताने वाले कई आंकड़े सबके सामने हैं। बेरोजगारी की दर सात फीसदी से ऊपर है। भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की बजाय कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। ध्यान रहे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर विनिर्माण का है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया योजना की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद अगर कृषि सेक्टर में रोजगार बढ़ रहा है तो वास्तविकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले कई सालों में पहली बार हो रहा है कि मनरेगा में रोजगार मांगने और करने वालों की संख्या बढ़ी है। यह भी देश की संगठित और असंगठित दोनों सेक्टर के रोजगार की कहानी बयान करता है। प्राइवेट थिंक टैंक 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' यानी सीएमआईई ने पिछले दिनों बताया कि ऐसे लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है जो नौकरी की तलाश ही नहीं कर रहे हैं। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में ऐसे लोगों की संख्या 45 करोड़ हो गई है, जो कामकाज करने की उम्र के हैं और किसी न किसी किस्म के रोजगार के योग्य हैं लेकिन नौकरी नहीं तलाश रहे हैं। भारत में कानूनी रूप से नौकरी करने की उम्र वाले लोगों की संख्या 90 करोड़ है, जिसमें से आधे लोग नौकरी ही नहीं तलाश रहे हैं क्योंकि उन्होंने नौकरी मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच समग्र श्रम भागीदारी 46 फीसदी से कम होकर 40 फीसदी हो गई। इस अवधि में दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने काम छोड़ा और सिर्फ नौ फीसदी योग्य आबादी को रोजगार मिला। देश की महज नौ फीसदी महिलाओं के पास काम है या वे काम की तलाश कर रही हैं।

सोचें, जहां रोजगार की ऐसी स्थिति है वहां अगर किसी एक सेवा में स्थायी और नियमित नौकरी की उम्मीद हो और उसमें अचानक सदियों पुराने भर्ती के नियमों को मनमाने तरीके से बदल दिया जाए तो युवाओं पर क्या बीती होगी? वे किस मन:स्थिति में होंगे। तभी यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि असली समस्या अग्निपथ योजना नहीं है, बल्कि असली समस्या नियमित नौकरी की कमी है।

अजीत द्विवेदी

संपादकीय

जनता आगे, पार्टियां पीछे

इस अनुभव के आधार पर यह साफ कहा जा सकता है कि जनता के रोजमर्रा के संघर्षों से राजनीतिक दलों का अब कोई नाता नहीं बचा है। पक्ष हो या विपक्ष- जनता के रोजमर्रा के संघर्षों की कसौटी पर वे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है।

पिछले पांच साल के चार जन आंदोलनों को याद कीजिए। 2018 में अनुसूचित जाति- जन जाति कानून को ढीला बनाने के मुद्दे पर दलित समुदाय के लोगों सड़कों पर उतरे और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। 2020 में किसानों ने मोर्चा संभाला, जो साल भर चलता रहा। अब 2022 में सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवानों ने अपना गुस्सा सड़कों पर आकर उतारा है। इन सभी आंदोलनों में एक आम पहलू यह है कि इन्हें संयोजित, संचालित और उन्हें नेतृत्व देने में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं रही। विपक्ष दल तब सक्रिय हुए, जब आंदोलन भड़क चुका था। तब भी उन दलों की भूमिका आंदोलन को समर्थन देने और उसके बहाने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने के अलावा और कुछ नहीं रही। लेकिन अपने-अपने कारणों से सड़क उतरने जन समूहों ने उसे ज्यादा तव्वजो नहीं दी। बल्कि किसान आंदोलन ने तो यह साफ नीति घोषित कर रखी थी कि उसके मंच पर किसी राजनेता को आने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस अनुभव के आधार पर यह साफ कहा जा सकता है कि जनता के रोजमर्रा के संघर्षों से राजनीतिक दलों का अब कोई नाता नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं।

क्या भाजपा के बिछाए जाल से निकल पाएगी शिवसेना ?

कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, बल्कि अक्सर तुकबंदी करता है। शिवसेना-कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी (एमवीए) की शुरुआत ही एनसीपी में नाकाम बगावात से हुई थी। ढाई साल बाद इस गठबंधन के संभावित अंत को शिवसेना में बगावत के रूप में परिभाषित किया जा रहा है।

वर्ष 2019 में राकांपा ने शिवसेना के साथ मिलकर भाजपा को मात देकर सत्ता पर कब्जा किया था। उसका बदला भाजपा ने वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे को बहला-फुसलाकर और राजनीतिक बाघ को फंसाकर शिकार किया है। क्या शिवसेना भाजपा के बिछाए जाल से निकल पाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है। हालांकि भाजपा के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण है। विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा दलबदल पर कानून की व्याख्या और उसके बाद के मामले अनिश्चितता का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हिंदुत्व के वोट के लिए शुरू हुई यह लड़ाई गुवाहाटी से मुंबई की विधानसभा तक पहुंचने से पहले अब अपेक्षा के अनुरूप ही अदालत में पहुंच गई है और सड़कों पर भी दिख सकती है। महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का यह हश्र राजनीतिक दलों के लिए कुछ सबक पेश

महाराष्ट्र सरकार का पतन एक महागठबंधन की इच्छा और उसके निर्माण के लिए जोखिम प्रबंधन के संबंध में सबक पेश करता है।

करता है और ध्यान देने योग्य कुछ सवाल उठाता है। कुछ समय पहले बंगाल चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ एक आम मोर्चा बनाने की बातें हो रही थीं और उसके केंद्र में ममता बनर्जी और शरद पवार थे। महाराष्ट्र सरकार का पतन एक महागठबंधन की इच्छा और उसके निर्माण के लिए जोखिम प्रबंधन के संबंध में सबक पेश करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा एमवीए गठबंधन के पतन का लाभ उठाएगी-इसके विरोधाभासों और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, जो कि अवसरवादी गठबंधनों के खिलाफ विश्लेषण का विषय होगा। राजनीतिक उद्यमिता और अवसरवाद के लिए एमवीए विश्लेषण का विषय है। तीनों दलों का एक साथ आना अटल बिहारी वाजपेयी की इस उक्ति को चरितार्थ करता था-कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इनमें से हर पार्टी एक दूसरे की कटु आलोचक रही है। मूल रूप से कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा समर्थित शिवसेना ने मुंबई से कांग्रेस को खदेड़ना शुरू किया और 1980 के दशक में हिंदुत्व के मुद्दे पर सवार होकर बड़ी ताकत के रूप में उभरी। इसका उदय 1988 में कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (एस) के विलय से हुआ, जिससे विपक्ष का स्थान खाली रह गया। कांग्रेस (एस), या पवार कांग्रेस, एनसीपी का पहला अवतार था, जिसका जन्म 1999 में कांग्रेस के %विदेशी नेतृत्व% के खिलाफ हुआ था। आगे का रास्ता आंदोलन और कानूनी लड़ाई वाला है। भाजपा प्लान ए और बी, दोनों से लैस है।

प्लान ए इस उम्मीद पर टिका हुआ है कि वह अपनी पसंद के विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करने, ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को सदन में विश्वास मत में हराने और देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर डबल इंजन सरकार चलाने के लिए नियुक्त करेगी और देवेंद्र फड़णवीस के बारे में सभी अटकलों को खत्म कर देगी। हालांकि, कुछ समय बाद, पार्टी यह लड़ाई सड़कों पर नहीं लड़ना चाहेगी, क्योंकि इस मामले में शिवसेना की जो पहचान है, उसे देखते हुए वह मुंबई में कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकती है। उसके बाद भाजपा का प्लान बी शुरू होगा और वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर गुजरात के साथ विधानसभा का चुनाव कराएगी।

शंकर अय्यर

मिला जुला

मुंबई में बड़ा हादसा

4 मंजिला इमारत गिरी, एक की मौत, 11 घायल

मुंबई। मुंबई में एक चार मंजिला बिल्डिंग गिर गई. मलबे में कई लोग दबे गए थे. रेस्क्यू के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें एक की मौत हो गई. जबकि 11 लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये हादसा कुर्ला के नाइक नगर में हुआ है. मौके पर दमकल की टीम और पुलिस पहुंच गई है. राहत और बचाव अभियान जारी है।

मुंबई के कुर्ला के नाइक नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मलबे में 20-25 लोगों के दबे होने की संभावना है. मौके पर दमकल की टीम और पुलिस मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 5 लोगों को निकाल लिया गया है।

मलबे से 5 लोगों को निकाला गया

महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि मलबे से 5 लोगों को निकाल लिया गया है और इन्हें अस्पताल ले जाया गया है. चारों बिल्डिंग को बीएमसी की ओर से नोटिस दिया गया था. फिर भी कुछ लोग वहां रह रहे थे. पहले प्रॉयरिटी है कि सभी लोगों को निकालें. मंगलवार की सुबह मिलकर लोगों को खाली कराएंगे और डिमोलिस कराएंगे. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब भी बीएमसी नोटिस दे तो जल्दी से खाली कर देना चाहिए, ताकि ऐसी घटना न हो।

राजावाड़ी अस्पताल के सीएमओ डॉ. पवार ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत हुई है. जबकि चैत बसपाल (36) की हालत स्थिर है. वहीं, आबिद अंसारी (26), गोविंद भारती (32), मुकेश मोरया (25), मनीष यादव (20) का इलाज चल रहा है. इसके अलावा, संतोष कुमार गौड़ (25), सुदेश गौड़ (24), रामराज रहानी (40), संजय माजी (35), आदित्य कुशवाह (19 साल) को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया.

कृषकों को ना होने पाए खाद बीज की कमी-मंत्री कवासी लखमा

सर्किट हाउस सुकमा में संक्षिप्त बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज सर्किट हाउस सुकमा में अधिकारियों की बैठक ली। इस संक्षिप्त बैठक में उन्होंने जिले में खाद बीज का भंडारण एवं वितरण, कृषि कार्यों, मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में कलेक्टर विनीत नंदनवार, सीईओ जिला पंचायत

दुर्गम क्षेत्रों में राशन भंडारण करें सुनिश्चित

डीएन कश्यप, वनमंडलाधिकारी जेएस रामचंद्र, एसडीएम सुकमा सुश्री प्रीति दुर्गम, तहसीलदार सुकमा प्यारेलाल नाग सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री कवासी लखमा ने जिले में मानसून की समीक्षा के दौरान कहा की जिले में अभी पिछले वर्ष की तुलना में कम वर्षा हुई हैए आगामी दिनों में वर्षा की संभावना है। अत्यधिक वर्षा के दौरान प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखे। उन्होंने कहा की ऐसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र जो वर्षा के कारण मुख्यमार्ग से अलग हो जाते हैए उन ग्राम पंचायतों में पर्याप्त मात्रा में राशन का भंडारण किया जावे। जिस पर खाद्य अधिकारी ने बताया की दूरस्थ क्षेत्रों में शत प्रतिशत खाद्यान भंडारण किया जा चुका है। कृषि कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने जिले में खाद, बीज के भंडारण और वितरण का संज्ञान लिया और अधिकारियों को आवश्यकता अनुरूप पूर्व में खाद, बीज की मांग करने को कहा ताकि कृषकों को उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया,डायरिया, सर्पदंश आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा रखने के निर्देश दिए हैं। ताकि आपात स्थिति में पीड़ित को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

कोरिया जिले में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात का पहला दिन बहरासी, रामगढ़ , रजौली क्षेत्र में

प्रदेश में किसानों की खुशहाली मेरा पहला उद्देश्य-भूपेश बघेल

जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश मुखिया भूपेश बघेल के प्रदेश भर के 90 विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरा को लेकर कोरिया जिला के तीन दिवसीय दौरे में जिला के वनांचल क्षेत्र भरतपुर जनकपुर विधानसभा के बहरासी, रामगढ़, रजौली में पहुंच कर शासन की चल रही योजनाओं के बारे में लोगों से जानकारियां साझा किया साथ ही योजनाओं से लोगो को किस प्रकार से आर्थिक लाभ मिल रहा इस पर चर्चा किया साथ ही

जनकपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा किया। आपको बता दें की प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीन दिवसीय दौरे पर कोरिया प्रवास पर है इस तीन दिन में जिले के तीनों विधानसभा

उप तहसील से लेकर नगर पंचायत के साथ अन्य कई मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की

मनेंद्रगढ़, जनकपुर भरतपुर, बैकुंठपुर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लोगों से बात करेंगे इसी क्रम में में आज भरतपुर जनकपुर विधानसभा के ग्राम बहरासि,रामगढ़, रजौली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए की जन हिताय योजनाओं की घोषणा किया।

'टेक्सास में त्रासदी'- ट्रक के अंदर 46 प्रवासी मृत मिले, कई अस्पताल में भर्ती

अमेरिका के टेक्सास से डरा देने वाली खबर सामने आई है. सैंट एंटोनियों शहर में एक ट्रक के अंदर 46 लोग मृत पाए गए हैं. कानून प्रवर्तन अधिकारी ने इस दिल दहला देने वाले वाकये के बारे में जानकारी दी है. वहीं शहर के अधिकारियों ने कहा कि यूएस-मेक्सिको सीमा पर मानव तस्करी की सबसे घातक हालिया घटनाओं में से एक है.

सैन एंटोनियो अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें ट्रक में 'शवों के ढेर' मिले. ट्रक में पानी का कोई निशान नहीं मिला. विभाग ने कहा कि ट्रेलर के अंदर पाए गए सोलह अन्य लोगों को हीट स्ट्रोक और थकावट के चलते अस्पतालों में ले जाया गया।

अस्पताल से आते ही एक्शन में राज्यपाल कोश्यारी

उद्धव सरकार से मांगा तीन दिन की फाइलों का हिसाब-किताब

मुंबई. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हॉस्पिटल से वापस लौटते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं. उन्होंने उद्धव सरकार से बीते तीन दिन की फाइलों का हिसाब-किताब मांग लिया है. कयास लगाये जा रहे हैं कि राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार के कुछ आदेशों को पलट भी सकते हैं. ऐसे में राज्यपाल और सीएम उद्धव के बीच की तल्खी और बढ़ सकती है. बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच भगत सिंह कोश्यारी को कोविड संक्रमण हो गया था. इसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था. लेकिन दो दिन पहले यानी 26 जून को वह डिस्चार्ज हो गये हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, राज भवन सचिवालय ने राज्य सरकार से कुछ फाइलों की डिटेल मांगी हैं।

मुख्यमंत्री ने बांकी नदी के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण संवर्धन के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की

भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को नगरवासियों ने बताया वृतांत,कलेक्टर की हुई सराहना

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर के भ्रमण और भेंट मुलाकात के दौरान विगत दिवस 26 जून को सरना एथनिक रिसोर्ट में जशपुर वासियों ने बांकी नदी के जीर्णोद्धार जल संरक्षण संवर्धन के सराहनीय कार्य की जानकारी दी।

लोगों ने बढ़ चढ़कर किया श्रम एवं अंशदान किया

उन्होंने बताया कि बांकी नदी को संरक्षित करने के लिए कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, जिला प्रशासन और जशपुर वासियों की जनसहभागिता से बांकी नदी को संरक्षित करने का सार्थक कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हीरूराम निकुंज, युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन, सुरेश गुप्ता, देवेन्द्र गुप्ता, शिवानंद मिश्रा उपस्थित थे। श्रमदान और अंशदान कर लगभग 3 किमी लम्बी बांकी नदी का जीर्णोद्धार कर दिया। जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। भेंट मुलाकात के दौरान बांकी नदी से जुड़े प्रतिनिधि मण्डलों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ मिलकर कलेक्टर जशपुर रितेश अग्रवाल की उपस्थिति में जल आंदोलन का विस्तृत वृतांत बताया। जिसे बहुत ही गम्भीरता से मुख्यमंत्री ने सुना और नागरिकों के इस अभियान को भरपूर सहयोग देने हेतु कलेक्टर रितेश अग्रवाल की सराहना भी की। जल आंदोलन के प्रतिनिधियों ने 18 किमी लम्बी बाँकी नदी का जीर्णोद्धार नरवा मिशन के तहत करने की मांग की जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहर्ष स्वीकार करते हुए इस सबन्ध में कलेक्टर जशपुर को निर्देश दिए साथ ही उन्होंने बाँकी नदी के उद्गम से लेकर संगम तक नदी के दोनों तटों पर वृक्षारोपण सहित जल ग्रहण क्षेत्र का समग्र उपचार करने का भी निर्देश दिया है। इस हेतु प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है।

जोहार छत्तीसगढ़ विशेष खबर

शोसल मीडिया ने नामजद अपशब्द प्रसारित किये जाने में सौंपा ज्ञापन

अरूण विश्वकर्मा के ऊपर उपरोक कृत्य का मामला मामला दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग

जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।

शोसल मीडिया ने नामजद अपशब्द प्रसारित किये जाने के संबंध में सौंपा ज्ञापन सब्जी व्यवसायी चन्दन गुप्ता को अरूण विश्वकर्मा द्वारा फेशबुक सोशल मीडिया में दोगला से संबोधित करते हुये पोस्ट डाला है। वही चन्दन गुप्ता ने चिरमिरी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान चन्दन गुप्ता ने बताया की अरूण विश्वकर्मा का उदेश्य मुझे अपमानित करना था और इसी आशय से अरूण विश्वकर्मा द्वारा मेरे नाम सहित दोगला सम्बोधित किया गया। जिससे मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंची। इस पोस्ट से मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। ज्ञापन सौप कार्यवाही की मांग की है।

दोगला अपशब्द से मैं क्षुब्ध एवं दुःखी हूं- चन्दन गुप्ता

एक सरंपच एवं तीन पंच के लिए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न

1085 मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत जिले में 1 सरपंच तथा 3 पंच पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। इस उप निर्वाचन में 1085 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उप चुनाव के लिए चुनाव प्रेक्षक संयुक्त कलेक्टर कवर्धा दीप्ती गौते ने आज मतदान केन्दों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वास राव म्हस्केए प्रेक्षक के लायजनिंग अधिकारी एवं प्रभारी खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर उपस्थित थे। जनपद पंचायत बेमेतरा कुल 210 मतदाताओं में से 152 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इनमें 72 पुरुष एवं 80 महिला शामिल है। इसी क्रम में विकासखण्ड नवागढ़ के कुल 1363 मतदाताओं में से 933 मतदाताओं ने अपने वोट डाले। इनमें 491 पुरुष एवं 442 महिला शामिल है। इस तरह पंचायत उप चुनाव में जिले का मतदान 69 प्रतिशत रहा। ज्ञात हो कि जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बाघुल में सरपंच पद के लिए मतदान हुआ। इसी प्रकार ग्राम पंचायत संबलपुर के वार्ड क्रमांक 11 में पंच पद के लिए एवं ग्राम पंचायत कामता के वार्ड क्रमांक 12 में मतदान हुआ। इसी तरह जनपद पंचायत बेमेतरा के ग्राम पंचायत कुसमी के वार्ड क्रमांक 04 में पंच पद के लिए मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ।

एक नजर

सायबर क्राईम का पिथौरा पुलिस ने किया जुर्म दर्ज

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

विवाह पूर्व एक युवती के मंगेतर को लगातार व्हाट्सएप पर गलत फोटो पोस्ट किए जाने की शिकायत पर जिले की पिथौरा पुलिस द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 509 ख के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम लाखागढ़ निवासी संतोष उर्फ संजय कुमार पिता गंगाराम सारथी द्वारा विगत 23 जून से 27 जून के बीच प्रार्थिया युवती के मंगेतर को उसके मोबाइल में युवती का गलत फोटो व्हाट्सएप मैसेज करने की शिकायत पर पिथौरा पुलिस ने जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुसवाड़ा सड़क दुर्घटना में घायलों को सहायता राशि स्वीकृत

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

कोन्टा तहसील अंतर्गत पुसवाड़ा के समीप हुए सड़क दुर्घटना में घायल पांच व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा. कोन्टा द्वारा जारी आदेश के अनुसार रंजित कविराज पिता तारकनाथ कविराज, शिवशंकर सारथी पिता बैनूराम सारथी, रामसिंह पिता वैजनाथ, सुशांत मण्डल पिता जितेन्द्र मण्डल एवं जितेन्द्र मण्डल पिता ज्योतिश मण्डल को 12 हजार 500 रुपए, कुल 62,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती की वरीयता सूची जारी

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

जिले में संचालित स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सुकमा, कोण्टा एवं छिन्दगढ़ में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों का पात्र-अपात्र सूची जारी कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी कर दी गई है। जिला के वेबासाईट के पर वरियता सूची का अवलोकन किया जा सकता है। पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

बालको ने स्थानीय छात्रों के लिए मासिक कौशल विकास शिविर लगाया

कोरबा । भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको ने क्षेत्र के पांच सरकारी स्कूलों के लगभग 250 छात्रों के लिए एक माह का शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया। बालको सीएसआर के प्रोजेक्ट कनेक्ट के तहत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, लाइफस्किल, डाइट एजुकेशन, साइबर क्राइम, व्यक्तित्व विकास, स्व-प्रबंधन, कंप्यूटर शिक्षा, संचार, प्रेरणा, खेल शिक्षा, कानून सत्र तथा नृत्य, संगीत, कला एवं शिल्प, करियर परामर्श तथा पशु बचाव आदि विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर रजनी कुजूर एवं सुमति बाई का बना राशन कार्ड

दोनों हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन को दिया धन्यवाद

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 जून को कुनकुरी विधासनभा के ग्राम पंमशाला में आयोजित जनचौपाल में आमजनों की शिकायतों को सुना एवं तत्काल निराकरण करने के निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए। इसी कड़ी में ग्राम पगुराबहार निवासी सुमति बाई एवं पण्डरीपानी सिसरिंगा निवासी रजनी कुजूर ने मुख्यमंत्री से राशनकार्ड बनवाने हेतु अपनी मांग रखी। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों हितग्राहियों का प्राथमिकता के साथ तत्काल राशन कार्ड तैयार कर हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों हितग्राहियों का तत्परता के साथ राशन कार्ड बना कर उपलब्ध कराया गया है। हितग्राही रजनी कुजूर एवं सुमति बाई ने कहा कि उनके मांग को मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया। जिस पर उनके निर्देश पर उन्हें राशन कार्ड मिल गया है। अब उन्हें शासन द्वारा प्रदाय किए जाने वाले राशन सामग्री आसानी से मिल जाएगी। दोनों हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।

कोड़ार की नहरों पर पुल-पुलियों के अवैध निर्माण की होगी जांच

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

कुछ समय पूर्व तक सिंचाई के लिए बनवाए गए सरकारी नहर नालियों पर पुल-पुलिया निर्माण की मांग आवागमन की आम सुविधा के लिए की जाती थी। तब लोगों को अपनी मांगों के चलते अधिकारियों और नेताओं तक दौड़ लगानी पड़ती थी।

फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद प्रशासकीय-तकनीकी स्वीकृति उपरांत ही पुल-पुलियों का निर्माण होता रहा है। लेकिन अब तो कोई भी, कहीं भी शासकीय नहर पर अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के लिए पुल पुलिया का निर्माण करवा सकता है। वह भी बिना किसी विभागीय अनुमति के खास बात यह है कि ऐसे मामलों में लिखित शिकायत के बाद भी जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी संज्ञान नहीं लेते। ऐसे ही एक मामले में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ के संयोजक ललित चंद्रनाहू द्वारा की गई शिकायत पर जल संसाधन विभाग महासमुंद के कार्यपालन अभियंता द्वारा कारवाई ना करने से नाराज किसान नेता चंद्रनाहूं छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग महासमुंद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी। ज्ञातव्य है कि शहीद वीरनारायन सिंह जलाशय कोड़ार परियोजना महासमुंद के नहरों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनेक स्थानों पर जल संसाधन विभाग बिना अनुमति प्राप्त किये पुल-पुलियों का निर्माण किया गया है। यह प्रक्रिया जारी है। इससे नहरों को क्षति पहुंच रही है और जल प्रवाह प्रभावित होने से खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है।

कार्यपालन अभियंता महासमुंद के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग

उक्त पुल-पुलिया ग्राम खरोरा से घोड़ारी और बिरकोनी तक नहरों में निर्मित मे है। इसी तरह ग्राम खरोरा एवं बेलसोंडा के मध्य नहर के बायें पार्श्व में एक व्यक्ति द्वारा धान की खेती कई वर्षो सें करते हुये अतिक्रमण किया गया है। इससे नहर का बंड प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त मुद्दे पर किसान नेता चंद्रनाहू ने कार्यपालन अभियंता महासमुंद के जांच.कार्यवाही हेतु पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर किसी तरह की कार्यवाही न होने से चंद्रनाहू ने छत्तीसगढ़ शासन के सचिव जल संसाधन को पत्र लिखकर कार्यपालन अभियंता महासमुंद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की है। कोड़ार जलाशय के नहर में अवैध पुल-पुलियों के निर्माण की शिकायत और कार्यपालन यंत्री जल संसाधन महासमुंद के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने को लेकर जल संसाधन विभाग मंत्रालय रायपुर के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को जांच हेतु अधिकृत किया गया है। कहा गया है किए प्रक्ररण का परीक्षण कर सुस्पष्ट अभिमत के साथ जांच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता के माध्यम से शासन को भेजे।

दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विश्वबंधु शर्मा के परिवार को राज्य शासन से मिली 5 लाख की सहायता राशि

जिला जनसंपर्क अधिकारी नूतन सिदार ने ललिता शर्मा को चेक सौंपा

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

संचार प्रतिनिधि कल्याण कोष तहत् जशपुर के दिवंगत दो पत्रकारों के परिवारों को 5.5 लाख कुल 10 लाख अब तक दी गई है

जशपुर जिले के दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विश्वबंधु शर्मा की पत्नी ललिता शर्मा को राज्य शासन द्वारा संचार प्रतिनिधि कल्याण कोष से पांच-पांच लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जनसंपर्क अधिकारी नूतन सिदार द्वारा जशपुर प्रेस क्लब के सहयोग से उक्त राशि का चेक ललिता शर्मा को प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि स्व. विश्वबंधु शर्मा लंबे समय से जशपुर जिले में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे थे। पिछले 28 दिसंबर को उनके आकस्मिक निधन के बाद परिजनों ने शासन से आर्थिक सहायता की मांग की थी। जिला जनसंपर्क अधिकारी नूतन सिदार व जशपुर प्रेस क्लब के पत्रकार साथियों की मदद से संचार प्रतिनिधि कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के लिए उनकी पत्नी ललिता शर्मा ने आवेदन कर शासन से आर्थिक सहायता की मांग की थी। अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक 3213 दिनांक 22 जून के अनुसार संचार प्रतिनिधि कल्याण कोष से स्वीकृत आर्थिक सहायता रुपये 05 लाख का चेक सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय जशपुर को भेजा गया है। विगत वर्ष 2021 में स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता पत्थलगांव विकासखण्ड के ग्राम तिलडेगा निवासी स्व.मनोज अम्बष्ट का विगत वर्ष 24 अप्रैल 2021 को कोरोना के कारण देहांत हो गया था। जिला जनसंपर्क जशपुर द्वारा उनकी पत्नी स्नेहा अम्बष्ट के आवेदनों को तत्काल जनसंपर्क संचालनालय भेजा गया और डेढ़ माह के अन्दर ही राज्य शासन ने उन्हें 5 लाख की सहायता राशि दिया था। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जनसंपर्क कार्यालय जशपुर में जिला जनसंपर्क अधिकारी नूतन सिदार द्वारा उक्त पांच लाख की आर्थिक सहायता राशि का चेक जशपुर प्रेस क्लब की उपस्थिति में स्वर्गीय विश्वबंधु शर्मा की पत्नी ललिता शर्मा को सौंपा गया। तत्काल आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में सतत सहयोग के लिए जशपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विकास पांडेय ने सभी पत्रकारों की ओर से सहायक जनसंपर्क अधिकारी नूतन सिदार के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर जशपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विकास पांडे समेत अमानुल्लाह मलिक, योगेश थवाईत, दीपक सिंह, रविन्द्र थवाईत, प्रशांत सहाय, मिथलेश गुप्ता अन्य पत्रकार, कर्मचारी व स्टाफ उपस्थित थे।

जशपुर जिले में प्रदेश का पहला उच्च स्तरीय फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब तैयार

मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के प्रवास के दौरान किया था शुभारंभ

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

खनिज न्यास निधि से 34 लाख की लागत से अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है

जशपुर के महिलाओं को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर के रंजीता स्टेडियम परिसर में स्थित फू ड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब में खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं पैकेजिंग केंद्र भवन का 27 जून को लोकार्पण किया। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जशपुर जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सहराहनीय पहल की जा रही है। समूह की महिलाओं को विभिन्न खाद सामग्री का पैंकिंग करने के लिए जिला प्रशासन ने खनिज न्यास निधि मद से 22.72 लाख रुपए की लागत खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं पैकेजिंग केंद्र से तैयार किया गया है। केन्द्र में लगभग 34 लाख रुपए लागत से विभिन्न मशीनों लगाया गया है। जशपुर जिले में प्रदेश का पहला उच्च स्तरीय लैब जिला प्रशासन ने तैयार किया है जिसमें विभिन्न उत्पादों के रॉ-मटेरियल को प्रसंस्कृत कर उन्हें विक्रय के लिए सी मार्ट में भेजा जा रहा है। खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं पैकेजिंग से समूह की महिलाओं के हाथों में रोजगार मिला है और वे सी-मार्ट में विक्रय हेतु भेजने के लिए खाद्य सामग्री काजू, आचार, पापड़, हल्दी मशाला, चायपत्ती, जीराफूल, जौवफूल चावल, आटा, रागी, कोदो-कुटकी बिक्री करने के लिए पैंकिंग का कार्य कर रही हैं।

राजस्थानी गुजराती भेड़ बकरी ऊंट चट कर रहे वनस्पति जंगलों को

हेमंत कुमार बंजारे

जोहार छत्तीसगढ़-कर्वधा।

कवर्धा वन मंडल के पंडरिया उप वन मंडल परिक्षेत्र के जंगलों में भेड़ बकरी चरवाहे हरे-भरे पौधों को लगातार काट रहे हैं। पंडरिया उप वन परिक्षेत्र के पूर्व,पश्चिम रेंज में जंगलों और मैदानी इलाकों में राजस्थान, गुजरात के ऊंट-भेड़ों का डेरा जमाए हुए है।

भेड़, एवम पशुओं को खिलाने के नाम पर हरे-पौधे वनस्पति को काट रहे हैं। एक ओर जहां करोड़ों रूपये लगाकर पौधारोपण करवाया जा रहा है वही दूसरी और राजस्थानी डेरा वाले भेड़-बकरियों का झुंड विनाश कर रहे हैं। वन माफि या भी वनों की कटाई कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। परिक्षेत्रवासियों में वन विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने मिल रहा है। बता दें कि अंचल में करीब कई सालों से राजस्थान गुजरात की भेड़-बकरी यहां पहुंच रही है ये बरसात के दिनों में जंगल में रहते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों को पहुंच जाते हैं। स्थानीय वनवासियों के अनुसार जिन स्थानों पर इनके भेड़, बकरी बैठते हैं वहां वनस्पति को काफ ी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में अभी चरौंटा नामक वनस्पति की अंचल में भरमार है। जहां लगातार इसके दोहन करने के कारण अब यह गिनती की बची हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्थान, के चरवाहे वर्षा व शीत ऋतु में जंगलों में रहते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की दिक्कत होने के कारण यह लोग मैदानी इलाकों में अपना डेरा जमाने लगते हैं। इन जंगलों में भेड़.बकरी व ऊंट का डेरा पंडरिया उप वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पूर्व,पश्चिम जंगलों में भेड़-बकरी बड़ी संख्या में है। साथ में इनके साथ ऊंट भी है। जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां इनका डेरा रहता है उस स्थान पर हरियाली पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस प्रकार जंगल को खत्म किया जा रहा है।

वनांचल के आदिवासियों ने बताया

अगर ऊंट भेड़ वालों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में वन और वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी। जंगल क्षेत्रों में वन विभाग के रेंजर और बिडगाड रहते हैं। लेकिन अंचल के लोगों को कभी भी इन अधिकारियों की सक्रियता जंगलों की सुरक्षा के लिए दिखाई नहीं देती। इसी का फ ायदा उठाते हुए चरवाहों ने वनांचल में अपना डेरा जमाना प्रारंभ कर दिया है। वनांचलवासी जब इसका विरोध करते हैं तो उनके द्वारा भी धौंस जमाते हुए विवाद करने पर उतारू हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वन विभाग के कर्मियों का इन्हें संरक्षण प्राप्त है। इसके कारण बेखौफ होकर जंगलों में घुसकर पेड़ पौधों को चारागाह बनाकर नष्ट कर रहे हैं।

राजस्व में रहते है चराते है जंगलो में

आप लोगों को बता दे ये लोग रहने के लिए राजस्व जमीन में रहते है और भेड़ बकरी ऊंट चराते हैं। जंगलो में ताकी बहाना बनाते बने हम तो राजस्व के जमीन में है। विभाग के जिमेदार लोगों को सब जानकारी होने के बाउजूद नहीं करते इनके ऊपर कोई कार्यवाही जो समझ से परे है। पंडरिया उप वन मण्डल अधिकारी से इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि बेचारे लोग जंगल में नहीं रहेंगे तो कहा जाएंगे यार इस प्रकार का जवाब देने लगे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। किन की संरक्षण प्राप्त है इन्हें।

एक नजर

सरायपाली में अवैध निर्माण पर होटल सिमरन का संचालन

बिना डायवर्सन के निर्माण पर एसडीएम से शिकायत

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

जिले के सरायपाली नगर में भंवरपुर मार्ग पर संचालित होटल सिमरन को लेकर सरायपाली एसडीएम को शिकायत प्रस्तुत किया गया है। शिकायत में कहा गया है किए उक्त भवन का निर्माण बिना नगर पालिका की अनुमति के अवैध रूप से कराया गया है। शिकायत में यह भी बताया गया किए नगर पालिका में उक्त निर्माण से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि उक्त भवन एक भाजपा नेता का है जो सालों तक नगर पालिका की सत्ता पर काबिज रहा है इसीलिए उसके द्वारा भवन निर्माण के लिए नगरपालिका के अनुमति की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई। खास बात यह है किए उक्त स्थल का बिना डायवर्सन के भवन निर्माण कर लिया गया है। सरायपाली से नागरिक बजरंग लाल सेन द्वारा एसडीएम के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर होटल सिमरन के संचालक से भवन निर्माण की अनुमति बाबत दस्तावेज प्रस्तुत करवाने निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। एसडीएम से दोषियों को उचित दंड दिए जाने का अनुरोध करते हुए यह भी कहा गया है किए प्रारंभिक जांच में अवैध निर्माण पाए जाने पर जब तक प्रकरण का निराकरण ना हो जाए। उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के व्यवसायिक उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा।

खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन स्टॉक की सीमा तय

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सभी प्रकार के खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों पर 31 दिसम्बर 2022 तक की अवधि के लिए अधिकतम स्टॉक संधारण सीमा निर्धारित की गई है। स्टॉक संधारण की सीमा सभी प्रकार के खाद्य तेल का कमीशन अभिकर्ता हेतु 30 क्विंटल, व्यापारी के लिए 500 क्विंटल, खुदरा दुकान वालों के लिए 30 क्विंटल एवं डिपों हेतु 1000 क्विंटल भण्डारण क्षमता के 90 दिनद्ध तक की अधिकतम स्टॉक निर्धारित किया गया हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार खाद्य तेल के बीज सभी प्रकार का कमीशन अभिकर्ता हेतु 100 क्विंटल, व्यापारी हेतु 2000 क्विंटल का अधिकतम स्टॉक निर्धारित की गयी है। यह सीमा खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसारद्ध है। उन्होंने बताया कि खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन का कोई भी व्यापारी किसी भी समय खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन का कोई भी स्टॉक उपरोक्त उल्लेखित मात्रा से अधिक भंडारण नहीं करेगा। करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आज कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के महानदी सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें उन्होंने रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना, सिंगल विलेज पेयजल योजना की कार्य प्रगति की जानकारी ली। बैठक में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त 24 सिंगल विलेज एवं 01 रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने तथा जल जीवन मिशन अंतर्गत 02 रेट्रोफिटिंग 20 सिंगल विलेज योजनाओं के लिए आमंत्रित ऑनलाइन निविदावार प्राप्त न्यूनतम दरों का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यपालन अभियंता एसके धकाते सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंची विधायक

नगरी । सेमरा (सिहावा) निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश कुमार साहू का 23 जून को अस्वस्थता के चलते रायपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके शोकाकुल परिवार से मिलने क्षेत्र के विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव पहुंची। उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर विधायक ने मृत आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को इस दु:ख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करने ईश्वर से प्रार्थना की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। उक्त अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी के अध्यक्ष भूषण साहू, साहू समाज के तहसील अध्यक्ष पुनीत राम साहू, क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता लखन लाल साहू, सेवादल अध्यक्ष अय्यूब खान, साहू समाज के वरिष्ठ खिलानंद साहू, कमल साहू सहित समाज जन एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बीडी महंत मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कार्य जल्द

सांसद ने चर्चा कर जानी स्थिति, दिए आवश्यक निर्देश

कोरबा । कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा है कि कोरबा जिले में स्थापित बिसाहूदास महंत मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए मान्यता देने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण पर है जो जल्द ही प्राप्त होने की संभावना है। सोमवार को कोरबा प्रवास के दौरान सांसद ने कोरबा मेडिकल कॉलेज के उप अधीक्षक डॉ रवि जाटवर को तलब कर उनसे तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। डॉ. जाटवर ने सांसद को बताया कि पिछले दिनों वर्चुअल बैठक में नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई थी जिसमें कुछ कमियां बताई जाकर इन्हें दूर करने के लिए निर्देश मिले थे। निर्देश के पालन में कमियों को दूर कर लिया गया है। चर्चा के उपरांत सांसद ने बताया कि बहुत ही जल्द कोरबा मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्राप्त होने वाली है और उसके साथ ही यहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कलेक्टर रानू साहू ने सांसद को बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम के द्वारा विगत दिनों निरीक्षण कर जमीन का मुद्दा बताया गया था।

कांग्रेस भाजपा के बीच अविश्वास प्रस्ताव का खेल महासमुंद के बाद सरायपाली में भी सिंहासन डोला

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

स्थानीय नगर पालिका के भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के पश्चात अब सरायपाली नगर पालिका में भी भाजपा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि सरायपाली के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अभी सम्मिलन की तिथि तय नहीं हुई है। और जैसा किए महासमुंद पालिका के अध्यक्ष ने कहा था उनके पास

जादुई आकंडा है और वे समय पे अपना कमाल दिखायेंगे। उसी तर्ज पर सरायपाली के पालिका अध्यक्ष ने भी दावा किया है किए उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होना तय है। भाजपा के अनेक पार्षद अभी से कांग्रेस में आने को तैयार है। कांग्रेस के अल्पमत होने पर भी अगर वे अध्यक्ष बने है तो इसके पीछे भाजपा वाले भाईयों का ही योगदान था और आगे भी बना रहे। इसलिये उन्हें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई चिंता नहीं है।

ज्ञातव्य है किए सरायपाली नगर पालिका में दलगत स्थिति की बात करे तो 15 पार्षदों वालें परिषद में भाजपा पार्षदों की संख्या 9 है जबकि कांग्रेस के 3 पार्षद व तीन अन्य पार्षद निर्दलीय है। बताया जाता है किए पिछले दिनों सराईपाली प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा होटल सिमरन में भाजपा पार्षदों की बैठक लेते हुए उन्हें लताड़ लगाई गई थी किए बहुमत के बाद भी भाजपा को विपक्ष में बैठना आखिर कैसे संभव हुआ। कांग्रेस का कब्जा है। समझा जा रहा है, इसी दौरान अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति तैयार की गई थी। जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

स्कूल गेम्स की तैयारी में जुटे खेलगांव के खिलाड़ी

जोहार छत्तीसगढ़-रतनपुर।

स्कूल गेम्स 2022-23 की शुरुआत जुलाई माह से प्रारंभ होने वाली है। बहुत जल्द वार्षिक खेल कलेंडर का रूप रेखा तैयार हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ओमकारा स्पोर्ट्स क्लब खेलगांव नवागांव के खिलाड़ी पदक जीतने को इरादे से बालक व बालिका वर्ग के खिलाड़ी खेल अभ्यास में जुट गए है। इस संबंध में जानकारी देते हुवे खिलाड़ियों के कोच ओमकार जायसवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूल गेम्स की तैयारी में खेलगांव नवागांव के खिलाड़ी सुबह शाम पानी टंकी खेलमैदान में सुबह 5 से 7 बजे व शाम को भी 5 से 7 बजे तक मैदान में अभ्यास कर

पसीना बहा रहे हैं दो साल कोविड महामारी की वजह से खिलाड़ी अपना खेल कौशल का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। जिनका मलाल आज भी खिलाड़ियों को है फि र से स्कूल गेम्स तय समय सीमा में प्रारंभ होने से खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई है और सभी खिलाड़ी मेहनत करने में जुट गए हैं इससे पहले भी खेलगांव के बालक व बालिका वर्ग के खिलाड़ी राज्य व रास्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है पानी टंकी खेलमैदान में प्रतिदिन विभिन्न खेल जैसे कबड्डी, कुश्ती, कुरास, एथलेटिक्स एव जुडो आदि खेलो का आ प्रैक्टिस किया जाता है अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों में बालक वर्ग में कौशल यादव, शत्रुहन बालिका वर्ग में रंभा जायसवाल आदि खिलाड़ी अभ्यास करते है इनको प्रैक्टिस कराने में खेल मैदान संरक्षक गुलाब सिंह श्याम का विशेष सहयोग रहता है।

कलेक्टर एवं एसपी ने ली जिले की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

मुख्यमंत्री छग शासन के निर्देशानुसार प्रति मंगलवार टीएल बैठक के पूर्व प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है इसी क्रम में 28 जून 2022 दिन मंगलवार को संयुक्त कार्यालय बेमेतरा के सभाकक्ष में जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह के द्वारा कानून/सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लिया गया। जिसमें बेमेतरा जिले की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन, डीएसपी राजेश कुमार झा, एसडीओपी राजीव शर्मा, बेमेतरा एसडीएम दुर्गेश वर्मा, नवागढ़ एसडीएम प्रवीण तीवारी, साजा एसडीएम धनराज मरकाम, संयुक्त कलेक्टर युगल किशोर उर्वशा, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव मस्के, डिप्टी कलेक्टर हीरा गवर्ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना चौकी प्रभारियों सहित प्रशासनिक एवं पुलिस के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आज कर्मचारी फेडरेशन के कर्मचारी रहेंगे एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर

जिलेभर के फारेस्ट सहित कई विभाग के दफ्तरों में दिखेगा बंद का असर

जोहार छत्तीसगढ़-देवभोग।

एकबार फिर छग कर्मचारी फेडरेशन एसोशियेशन के सभी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे। पिछले बार वन विभाग के कर्मचारी सरकार के वादे के मुताबिक लगभग महिनेभर लम्बी हड़ताल तोड़कर दफ्तर लौटे थे।

हड़ताल स्थगित को माहभर बीत गये पर ना उनको किये वादे पूरे हुये और ना उनकी वेतन विसंगति, केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता,पदोन्नति की मांग पूरी हो सकी। सरकार के रवैये को लेकर वन कर्मी फिर से हुंकार भर रहे है और कल एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल से इसकी शुरूवात कर रहे है। हालांकि वन कर्मचारी अपने वेतन विसंगति को लेकर वर्षो से लड़ रहे हैं। सरकार आयी चुनाव के बाद वादे भी हुये पर इनकी मांग जस का तस रह गया।

गरियाबंद जिले के दफ्तरों में होगा सन्नाटा

गरियाबंद वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डोमार सिंह कश्यप और सचिव दिनेशचन्द्र पात्र ने संयुक्त बयान में कहा कलमबंद हड़ताल का असर जिलेभर के पूरे दफ्तरो में दिखेगा। फेडरेशन के सभी कर्मचारी जिसमे कई विभाग शामिल है इनके सहित वनकर्मीयो के हड़ताल में चले जाने से सरकारी कामकाज भी ठप्प पड़ जायेगा और इनके एक दिन के हड़ताल मे भी कई विभागीय कार्य पिछड़ जायेंगे।

इसके बाद फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में

राज्यभर के समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अनुसार राज्यभर में अनिश्चित कालीन हड़ताल को लेकर तैयारी चल रही है और यदि कलम बंद के बाद भी उनके मुख्य मांगों को अनसुनी की गयी तो फेडरेशन लम्बी लड़ाई लड़ने को तैयार है।केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता जो इनकी प्रमुख मांग है उसे सरकार आज तक पूरी नहीं कर सकी है।

जोहार छत्तीसगढ़ विशेष खबर

लोहारडीह की महिलाओं ने की संसदीय सचिव से मुलाकात, रंगमंच व पहुंच मार्ग की ओर कराया ध्यानाकर्षित

रंगमंच के लिए डेढ़ लाख की घोषणा, पहुंच मार्ग के लिए अफसरों से चर्चा कर उचित पहल का दिया आश्वासन

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

लोहारडीह की महिलाओं ने संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर गांव में रंगमंच निर्माण के साथ ही परसापानी से डेगना नारा पहुंच मार्ग निर्माण की ओर ध्यानाकर्षित कराया। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने तत्काल रंगमंच निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं पहुंच मार्ग के लिए फारेस्ट की जमीन होने के कारण अफ सरों से चर्चा कर उचित पहल करने का आश्वासन दिया। मंगलवार को ग्राम पंचायत लोहारडीह की इंदुमती निषाद, गौरी यादव, मिथलेश्वरी निषाद, नर्मदा बाई, दिप्ती ठाकुर, शकुंतला, रेवती बाई, गैंदी बाई, राम बाई, तुलसीबाई, हेमीन निषाद,

आसमती ध्रुव, सेतकुमारी, इंदुबाई, चुनेश्वरी, पूर्णिमा बाई, नूतन बाई, मानकी बाई आदि संसदीय सचिव निवास पहुंचकर संसदीय सचिव चंद्राकर से मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि ग्राम पंचायत लोहारडीह के वार्ड क्रं सात पेंड्राडीह में रंगमंच निर्माण की जरूरत है। रंगमंच नहीं होने से विभिन्न आयोजनों में काफ ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यहां रंगमंच निर्माण की मांग रखी। इसी तरह महिलाओं ने वार्ड क्रं 15 परसापानी से डेगना नारा पहुंच मार्ग की जरूरत बताई। उन्होंने बताया कि पहुंच मार्ग नहीं होने से काफ ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में आवाजाही में काफी दिक्कतें आती है। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने विधायक निधि से रंगमंच निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं पहुंच मार्ग के लिए वन विभाग के अफ सरों से चर्चा कर उचित पहल करने का आश्वासन दिया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक नारायण बाईन, द्वारा आसमा पब्लिसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित कर मेडरमार कालोनी, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित।
संपादक -**नारायण बाईन,** फोन -फैक्स 07766299001, मो, 9479177711, 7489419194 Email-joharchhattisgarh@gmail.com, joharchhattisgarh@yahoo.co.in